सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-22 22 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2017 मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष कुल पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रुपये

महान नवम्बर क्रान्ति की सीखों को याद करते हुए शताब्दी वर्ष पर देश भर में जनसभाएं और जुलूस

रूस में महान समाजवादी क्रांति महान लेनिन के नेतृत्व में नवम्बर 1917 में सफल हुई थी। महान नवम्बर क्रान्ति की परम्परा को आग बढ़ाते हुए देश भर में इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इनमें बहुत बड़ी तादाद में मेहनतकश तबके के लोग जुट रहे हैं। जनसभाएं, संगोष्ठी, सेमिनार, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जलूसों का सिलसिला जारी है। कार्यक्रम की शुरूआत कॉ. शिवदास घोष पर रचित गान से हुई और समापन अन्तर्राष्ट्रीय गान से हुआ।

दिल्ली : सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की दिल्ली राज्य कमेटी के तत्वावधान में 7 नवम्बर को महान नवम्बर समाजवादी क्रांति की सौवीं वर्षगाँठ के अवसर पर मण्डी हाऊस से संसद मार्ग तक एक जुलूस निकाला गया तथा संसद मार्ग पर एक जनसभा आयोजित की गई। सभा को एसयूसीआई(सी) के दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्राण शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में

संबोधित किया। एआईयूटीयूसी के दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉ. हरीश त्यागी, एआईडीवाईओ की दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉ. प्रकाश सैनी, एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य सचिव कॉ. रितु कौशिक, एआईडीएसओ के दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉ. प्रशांत कुमार, सेव एज्यूकेशन कमेटी से प्रो. नरेन्द्र शर्मा और मेडिकल सर्विस सेंटर से डा. जे. मुर्मु ने सभा को संबोधित किया। सभा का संचालन एसयूसीआई(सी) के दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य कॉ. रमेश शर्मा ने किया।

दिल्ली के विभिन्न इलाकों से मजदूर-कर्मचारी, छात्र-नौजवानों तथा महिलाएं सभा में आई। वक्ताओं ने कहा कि यह क्रान्ति विश्व इतिहास में युगांतकारी घटना थी। इसने यह साबित कर दिखाया था कि धरती पर एक ऐसे समाज की स्थापना हो सकती है जहाँ इन्सान के द्वारा इन्सान के शोषण का पूर्ण खात्मा संभव है।

रूस में क्रांति के बाद एक ऐसे समाज की स्थापना हुई जहाँ छात्रों को हर स्तर पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त थी, चाहे वह महिला हो या पुरुष, बेरोजगारी पूर्णतः खत्म कर दी गई थी। महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान किया गया था। महिलाओं और पुरुषों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। वेश्यावृत्ति, भुखमरी, भिक्षावृत्ति जैसी समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से खत्म कर दिया गया था। किसानों पर होने वाले दमन को खत्म कर खेती के उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल कर उनकी दशा में सुधार लाया गया था। रूसी समाज उन सभी समस्याओं से मुक्त था, जो समस्याएँ आज हम अपने देश में देख रहे हैं। आज मरणासन्न पूँजीवादी व्यवस्था जो अपनी अंतिम साँसे गिन रही है, स्वयं को बचाने के लिए फासीवाद का रास्ता अख्तियार करती जा रही है। इसके कारण समाज के हर तबके पर आज पूँजीपतिपरस्त भाजपा सरकार का दमन चक्र चल रहा है। शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण के चलते मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार के नए अवसर पैदा करने की बजाय सरकार रोजगारों को छीन रही है। पिछले तीन सालों में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। गरीबी और भुखमरी अपने चरम पर पहुँच चुकी है। कुपोषण में भारत का स्थान विश्व में सबसे ऊपर है। 72% बच्चे तथा 52% महिलाएँ खून की कमी की शिकार हैं। महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों के रिकॉर्ड को देखने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश की जीवन रेखा कहे जाने वाले किसान आत्महत्याएँ करने पर मजबूर हैं।

वक्ताओं ने कहा कि ऐसे बदतर हालातों में सिर्फ समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के सिवा देश की मेहनतकश जनता के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आज महान रूसी क्रांति से सीख लेकर एक सही क्रांतिकारी पार्टी के बैनर तले क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है तभी पूँजीपतियों के शोषण-दमन से स्वयं को बचा सकते हैं और समाजवादी क्रान्ति के जरिये पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर शोषणहीन व्यवस्था, समाजवाद कायम कर सकते हैं।

रोहतक (हरियाणा) : क्रान्तिकारी पार्टी - एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) ने ऐतिहासिक महान नवम्बर

(शेष पृष्ठ 4 पर)

रोहतक : महान नवम्बर क्रान्ति के 100 साल पूरे होने पर शहर में जुलूस निकालते हुए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के कार्यकर्ता

सरकार की मजदूर-विरोधी, जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संसद पर तीन दिवसीय श्रमिक महापड़ाव ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी का आह्वान

नई दिल्ली : एआईयूटीयूसी सहित 10 केन्द्रीय श्रम संगठनों ने अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में और सरकार की मजदूर-विरोधी, जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 8 अगस्त 2017 को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में श्रमिकों के विशाल सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण फैसले लिये थे। पहले चरण में देश के सभी राज्यों और औद्योगिक केन्द्रों में सम्मेलन आयोजित करते हुए 9 से 11 नवम्बर 2017 तक संसद के सामने देश भर के मजदूरों का तीन दिवसीय महापड़ाव किया जाएगा। यदि फिर भी सरकार मजदूर-विरोधी, जनविरोधी नीतियों का हमला जारी रखती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जायेगी। उसी फैसले को लागू करते हुए 9 से 11 नवम्बर तक संसद मार्ग पर मजदूर-कर्मचारियों का 3 दिन का महापड़ाव सम्पन्न हुआ।

यह कई मायनों में महत्वपूर्ण था। एक थी इसकी विशालता। लगातार तीनों दिन इसमें लगभग एक लाख मजदूर-कर्मचारियों ने शिरकत की। दूसरी थी इसकी व्यापकता। इन तीन दिनों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों और बड़े-बड़े उद्योगों एवं सेवाओं जैसे कोयला, इस्पात, परिवहन, पेट्रोलियम, बिजली, बन्दरगाह, इन्जीनियरिंग, निर्माण, स्कीम वर्कर, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी, रेलवे, बैंक, बीमा, रक्षा उत्पादन के कर्मचारियों से लेकर असंगठित तथा खेतीहर मजदूर तक सभी इसमें शामिल हुए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण थी इसमें भाग लेने वाले मजदूर-कर्मचारियों का काबिले तारीफ अनुशासन और जोश-खरोश। संसद मार्ग पर तीन दिन तक मजदूरों के बिरादराना सहयोद्धा होने का अनूठा नजारा देखने को मिला। 12 सूत्री मांगों के नारों में मजदूर-कर्मचारियों का उत्साह-उमंग साफ झलकता था। इन मांगों में शामिल थी श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर मजदूरों के अधिकारों में कटौती बंद की जाए, महंगाई रोकी जाए, बढ़ती बेरोजगारी की रोकथाम की जाए, मूल्य सूचकांक से जोड़ कर 18000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन दिया

(शेष पृष्ठ 2 पर)

संसद मार्ग पर तीन दिवसीय श्रमिक महापड़ाव में उमड़े जन सैलाब का एक दृश्य

अनिश्चितकालीन हड़ताल ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

जाए, सभी को कम से कम 3000 रुपये मासिक पेन्शन दी जाए, स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए, स्थायी कामों में ठेका प्रथा बंद हो, श्रम कानूनों का सख्ती से पालन हो, सरकारी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का विनिवेशीकरण बंद किया जाए, बोनस, ईएसआई, पीएफ कानून में सभी सीलिंग समाप्त की जाएं, आवेदन के 45 दिन के अन्दर यूनियन पंजीकृत की जाए आईएलओ कन्वेन्शन नं. 87 और 98 का भारत सरकार अनुमोदन करे।

पूरे कार्यक्रम का संचालन करने के लिए बनी पांच सदस्यीय कमेटी में एआईयूटीयूसी की तरफ से सचिव मण्डल सदस्य कॉमरेड रमेश शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर दिन तीन सत्र हुए।

9 नवम्बर को पहले सत्र में केन्द्रीय श्रम संगठनों के नेताओं ने और अन्य दो सत्रों को विभिन्न फैडरेशनों के नेताओं ने धरने को सम्बोधित किया।

पहले सत्र में एआईयूटीयूसी के सचिवमण्डल सदस्य कॉ. सत्यवान, इंटक के अशोक सिंह, एटक के गुरुदास दासगुप्ता, एचएमएस के एच.एस. सिद्धू, सीटू के तपन सेन, टीयूसीसी के जी. देवासजन, सेवा की मनाली, एआईसीसीटीयू के राजीव डिमरी, एलपीएफ के शम्मुघम और यूटीयूसी के अशोक घोष ने धरने को सम्बोधित किया। सभा का संचालन सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को लेकर गठित अध्यक्षमण्डल ने किया। इसमें एआईयूटीयूसी के सचिवमण्डल सदस्य कॉ. रमेश शर्मा शामिल थे। दूसरे सत्र में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और सरकारी कर्मचारियों की फैडरेशनों के नेताओं ने धरने में अपनी बात रखी। केन्द्र व राज्य सरकारों व स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के ज्वाइंट प्लेटफार्म ऑफ एक्शन (जेपीए) के अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह दहिया ने और तीसरे सत्र में ऑल इण्डिया बैंक इम्प्लाइज यूनिटी फोरम के अध्यक्ष कॉ. विजयपाल सिंह ने धरने को सम्बोधित किया।

10 नवम्बर को पहले सत्र में अध्यक्षमण्डल में एआईयूटीयूसी की ओर से कॉ. विजयपाल सिंह रहे और वक्ता कॉ. सत्यवान थे। दूसरे सत्र में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रतिनिधि बोले। इसमें अध्यक्षमण्डल में एआईयूटीयूसी के हरियाणा राज्य सचिव कॉ. हरिप्रकाश रहे और वक्ता कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स कॉन्फैडरेशन ऑफ इण्डिया के नेता कॉ. रामफल थे। तीसरे सत्र में अध्यक्षमण्डल में एआईयूटीयूसी के कॉ. रमेश शर्मा रहे और वक्ता एआईयूटीयूसी के दिल्ली राज्य सचिव कॉ. मैनेजर चौरसिया रहे।

संसद के सामने मजदूरों के महपड़ाव को संबोधित करते हुए कॉ. सत्यवान

11 नवम्बर को तीसरे और अन्तिम दिन की शुरूआत में इंटक के अध्यक्ष जी. संजीवैया रेड्डी ने संघर्ष के अगले चरण के कार्यक्रमों का एक प्रस्ताव रखा। इनमें पहला था जनवरी 2018 के प्रथम सप्ताह तक जिला स्तरीय संयुक्त सम्मेलन आयोजित करना। दूसरा था जनवरी के अन्तिम सप्ताह में जिला स्तरीय 'सत्याग्रह' आयोजित करना। तीसरा था जब भी सरकार निजीकरण का कदम उठाये सैक्टोरल/इण्ड्रस्टीयल स्तर की संयुक्त हड़ताल करना। चौथा था केन्द्रीय बजट में यदि मजदूर-विरोधी कदम उठाएं जायें तो बजट के दिन विरोध प्रदर्शन करना। प्रस्तावों में यह भी रेखांकित किया गया कि यदि सरकार अपने मजदूर-विरोधी रवैये में बदलाव नहीं लाती है तो केन्द्रीय श्रम संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। इस प्रस्ताव का समर्थन एटक के महासचिव गुरुदास दासगुप्ता, एचएमएस के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धु, सीटू के महासचिव तपन सेन, एआईयूटीयूसी के सचिवमण्डल सदस्य कॉ. रमेश शर्मा समेत टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी के नेताओं ने किया। पहले सत्र में अध्यक्षमण्डल में एआईयूटीयूसी की ओर से कॉ. हरिप्रकाश रहे। दूसरे सत्र में स्कीम वर्करों के प्रतिनिधि बोले। इसमें अध्यक्षमण्डल में एआईयूटीयूसी का प्रतिनिधित्व कॉ. मैनेजर चौरसिया ने किया। आंगनवाड़ी इम्प्लाइज फैडरेशन ऑफ इण्डिया (एईएफआई) की अध्यक्ष कमलेश चहल वक्ता थी। तीसरे सत्र में अध्यक्षमण्डल में झारखण्ड की आंगनवाड़ी कर्मियों की नेत्री श्रीमती बीना सिन्हा थी और वक्ता थी आशा फैडरेशन ऑफ इण्डिया की ओर से दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसियेशन (दावा) की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनू।

कांग्रेस की यूपीए सरकार के शासनकाल से ही घोर जनविरोधी विनाशकारी उदारीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। बीजेपी उसी की निरन्तरता में इसे लागू कर रही है। दोनों के ही शासनकाल में इन मांगों को लेकर देशव्यापी हड़तालें हुई लेकिन कांग्रेस की तरह ही बीजेपी सरकार भी कारपोरेट घरानों के वर्ग स्वार्थ में मजदूर-कर्मचारियों की इन जायज मांगों की न केवल अनदेखी कर रही है, बल्कि उससे भी तेज हमले कर रही है। इसलिए देशव्यापी जोरदार आन्दोलन गठित करने की जरूरत है। पूंजीवादी बाजार व्यवस्था घोर संकटग्रस्त है। सालों साल से शोषण करते आ रहे धनकुबेर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। सरकार पूंजीपतियों के संकट का सारा बोझ मजदूर-किसानों पर डाल देने पर तुली हुई है। पूंजीपति वर्ग का कहना है कि उनको चीजों के दाम बढ़ाने, मजदूरों की छंटनी करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। सरकार का जन कल्याण और जन सेवा से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इसी का नाम उन्होंने 'सुधार' रखा हुआ है। इन मजदूर-विरोधी नीतियों से मजदूर-कर्मचारियों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। तभी से उनका संघर्ष जारी है। इसमें अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। यह कार्यक्रम अभूतपूर्व सफल रहा।

कॉ. रमेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत गीत 'यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा' के साथ मजदूरों के तीन दिवसीय महापड़ाव का समापन हुआ।

संसद के सामने मजदूरों के महापड़ाव को संबोधित करते हुए कॉ. रमेश शर्मा

केरल में यथोचित ढंग से मनाया महान नवम्बर क्रांति शताब्दी समारोह

त्रिवेन्द्रम (केरल) : एसयूसीआई (सी) की केरल राज्य कमेटी के तत्वावधान में महान नवम्बर क्रांति शताब्दी समारोह 3-4 और 5 नवंबर को पुथारीक्कण्डम मैदान, त्रिवेन्द्रम में यथोचित ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के भाग के रूप में मानवासक्षी प्रदर्शनी, जुलूस, जनसभा, सेमिनार, संगीत गोष्ठी, कवि सम्मलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम किये गये।

इतिहास और नवम्बर क्रांति के पाठ पर एक फोटो-पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन, पार्टी के राज्य कमटी के सदस्य कॉ. एस. राजीवन द्वारा 3 नवंबर को किया गया। शहर में सुसज्जित और उत्साहवर्धक जुलूस निकाला गया जो थंपनूर से शुरू हुआ और पुथारीक्कण्डम मैदान में जाकर समाप्त हुआ। जुलूस के सामने, कोमसोमोल कॉमरेड की एक टोली ने लाल झंडे और लेनिन और स्टालिन के चित्रों के साथ मार्च किया। पार्टी के केरल राज्य कमेटी के सदस्यों के नेतृत्व में जुलूस में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। जब जुलूस सभा स्थल पर पहुंचा तब संगीत दल द्वारा जनगीत प्रस्तुत किए गए।

शाम को पार्टी के केरल राज्य सचिवमण्डल सदस्य, कॉ. वी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता में सभा शुरू हुई। पार्टी के केंद्रीय स्टाफ और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य सचिव कॉ. के. श्रीधर ने सभा का उद्घाटन किया। पार्टी के राज्य सचिवमण्डल के सदस्य कॉ. जीएस पद्मकुमार और जयसेन जोसफ और त्रिवेन्द्रम जिला सचिव कॉ. आर. कुमार ने भी बात रखी। सभा इंटरनेशनेल के साथ शुरू हुई और जीएस गाने के साथ समाप्त हुई। सभा के बाद एक मशहूर फिल्म 'बैलड ऑफ द सोल्जर' दिखाई गई।

त्रिवेन्द्रम : सभा को संबोधित करते हुए कॉ. के. श्रीधर

4 नवंबर को एक कवि सम्मेलन किया गया जिसमें शहर के कई कवियों ने उनकी कविताएं पढ़ीं। इसका उद्घाटन प्रसिद्ध कवि डॉ. देशमंगलम रामकृष्णन ने किया और देशभमानी गोपी ने अध्यक्षता की।

शाम को फासीवाद के खिलाफ एक सांस्कृतिक बैठक आयोजित की गई जिसमें केरल के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। इसका उद्घाटन सीपीआई (एम) के पूर्व जिला सचिव और एक प्रसिद्ध प्रगतिशील लेखक पीरप्पनकोड मुरली द्वारा किया गया और एसयूसीआई (सी) के राज्य कमेटी सदस्य कॉ. टी.के. सुधीर कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। *विश्व शांति के खिलाफ साम्राज्यवादी खतरे* पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। कॉमरेड के. श्रीधर ने इसका उद्घाटन किया। इसमें सीपीआई के केंद्रीय सचिवमण्डल सदस्य कॉ. पैनियन रवींद्रन, आरएमपीआई के केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉ. के.एच. हरिहरन, एमसीपीआई (यू) के राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉ. वी. एस. राजेंद्रन, एसयूसीआई (सी) के राज्य कमेटी के सदस्य कॉ. ए. शेखर और अखिल भारतीय साम्राज्यवाद-विरोधी फोरम के जिला संयोजक कॉ. जी.आर. सुभाष ने बात रखी। एसयूसीआई (सी) के सचिवमण्डल सदस्य जी.एस. पद्मकुमार ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की

8 बजे एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शहर के कई गायकों और कलाकारों ने भाग लिया।

5 नवंबर को विश्व *सिनेमा पर सोवियत सिनेमा के प्रभाव* विषय पर एक संगोष्ठी की गई जिसका प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक के.पी.कुमारन ने उद्घाटन किया। प्रमुख फिल्म आलोचकों एम.एफ.थॉमस, विजयकृष्णन और नीलन ने संगोष्ठी में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी की राज्य कमेटी के सदस्य कॉ. वी.के. सदानंद ने की।

समाजवादी शिक्षा, विज्ञान द्वारा रचे गये नये इन्सान और महिलाओं की मुक्ति विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार गौरीदासन नायर ने किया। यह एआईएमएसएस के राज्य सचिव शैला के. जॉन की अध्यक्षता में हुई। स्त्री रक्षा समिति की राज्य संयोजक मिनी के. फिलिप, विज्ञान लेखक प्रोफेसर सी.पी. अरविन्दक्षण, लेखक प्रोफेसर विश्वासमंगलम सुंदरेशन, अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति के राज्य सचिव एम. शाजर खान और एआईडीएसओ की राज्य अध्यक्ष बिनू बेबी ने बात रखी। समापन सत्र में कॉमरेड आर. कुमार ने अध्यक्षता की। पार्टी के राज्य सचिवालय सदस्य, कॉमरेड्स जैइसन जोसेफ और जी.एस.पद्मकुमार ने बात रखी।

भारतीय मनीषियों की नजर में
रूस का समाजवाद

रूस ने सर्वहारा क्रान्ति के जरिये किया है दुनिया की संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस

स्तालिन और उनके समर्थक रूस के समाजवाद को सफलतामण्डित करने के लिए अभियान चला रहे हैं ताकि वे दूसरे देशों को प्रेरित कर सकें।...

आज अगर यूरोप में ऐसा कोई एकमात्र व्यक्ति है जिसके हाथों में आगामी कई दशकों के लिए यूरोपीय राष्ट्रों का भाग्य बदा है, तो वे हैं मार्शल स्तालिन। इसलिए भविष्य में सोवियत यूनियन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा उनकी ओर उद्वेग लेकर पूरा विश्व और सर्वोपरि पूरा यूरोप ताक रहा है।

हम सभी जानते हैं कि 17वीं सदी में इंग्लैण्ड ने संवैधानिक और गणतांत्रिक सरकार की धारणा लागू करने के जरिये विश्व सभ्यता में एक उल्लेखनीय योगदान दिया था, ठीक उसी तरह अठारहवीं सदी में फ्रांस ने स्वतंत्रता समता विश्व-भाईचारे के आदर्श के जरिये दुनिया की संस्कृति में एक अद्‌भुत योगदान के हस्ताक्षर रख दिये थे। उन्नीसवीं सदी में जर्मनी ने अपने मार्क्सीय दर्शन के जरिये उल्लेखनीय रूप से विश्व सभ्यता को योगदान दिया था। बीसवीं सदी में रूस ने सर्वहारा क्रान्ति, सर्वहारा सरकार और संस्कृति के क्षेत्र में देन के जरिये संसार की संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध किया है।

...सन्देह नहीं कि हम राष्ट्रीयतावादी हैं। किन्तु हम अन्तर्राष्ट्रीयतावादी भी हैं। हम कह सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि कोई राष्ट्रीयतावादी नहीं हो तो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अधिकारी नहीं हो सकता। विश्व की मुक्ति भारत की आजादी पर निर्भर करती है। जब तक एक भी राष्ट्र गुलामी की हालत में रहेगा, तब तक अन्तर्राष्ट्रीयतावाद विकास हासिल नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गुलाम राष्ट्र को ही दु:ख उठाने पड़ते हैं, जिस राष्ट्र ने उसे गुलाम में तब्दील किया है, उसे ज्यादा दु:ख उठाने पड़ते हैं। दुनिया की भलाई के लिए हमें सभी राष्ट्रों की आजादी चाहिए। पृथ्वी पर स्वतंत्रता, समानता और मैत्री कायम करना ही वह एकमात्र रास्ता है।

लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि समाजवाद कायम नहीं हो जाता

शहीद भगत सिंह

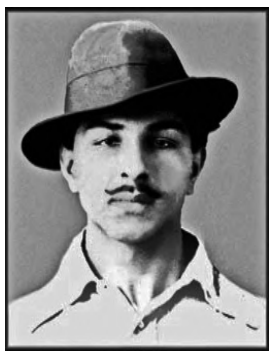

क्रान्ति से हमारा अभिप्राय है : अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन।

समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूँजीपति हड़प जाते हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने-दाने के लिए मुहताज हैं। दुनियाभर के बाजारों को कपड़ा मुहैया करने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के तन ढँकनेभर को भी कपड़ा नहीं पा रहा है। सुन्दर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ई स्वयं गन्दे बाड़ों में रहकर ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर जाते हैं। इसके विपरीत समाज के जोंक शोषक पूँजीपति जरा-जरा-सी बातों के लिए लाखों का वारा-न्यारा कर देते हैं।

यह भयानक असमानता और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की ओर लिये जा रहा है। यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती। स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर रंगरेलियाँ मना रहा है और शोषकों के मासूम बच्चे तथा करोड़ों शोषित लोग एक भयानक खड्ड के कगार पर चल रहे हैं।

आमूल परिवर्तन की आवश्यकता

सभ्यता का यह प्रासाद यदि समय रहते सँभाला न गया तो शीघ्र ही चरमराकर बैठ जायेगा। देश को एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और जो लोग इस बात को महसूस करते हैं उनका कर्त्तव्य है कि साम्यवादी सिद्धान्तों पर समाज का पुनर्निर्माण करें। जब तक यह नहीं किया जाता और मनुष्य द्वारा मनुष्य का तथा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं, समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक मानवता को उसके क्लेशों से छुटकारा मिलना असम्भव है और तब तक युद्धों को समाप्त कर विश्व-शान्ति के युग का प्रादुर्भाव करने की सारी बातें महज ढोंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। क्रान्ति से हमारा मतलब अन्ततोगत्वा एक ऐसी समाज-व्यवस्था की स्थापना से है जो इस प्रकार के संकटों से बरी होगी और जिसमें सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य सर्वमान्य होगा। और जिसके फलस्वरूप स्थापित होने वाला विश्व-संघ पीड़ित मानवता को पूँजीवाद के बन्धनों से और साम्राज्यवादी युद्ध की तबाही से छुटकारा दिलाने में समर्थ हो सकेगा। (बमकाण्ड पर सेशन कोर्ट में बयान 6 जून, 1929)

सोवियत रूस की उन्नति

प्रेमचंद

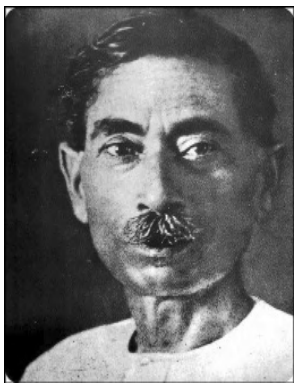

सोवियत रूस के पंचसाला कार्यक्रम का फल आशातीत हो रहा है। एक अंग्रेज पत्रकार ने वहां की वर्तमान दशा का पांच साल पहले की हालत से तुलना करते हुए लिखा है कि रूस में नये-नये नगरों और कस्बों की बाढ़-सी आ गयी है। कितने ही गांव, जहां सौ दौ सौ आदमी रहते थे वहां अब जनसंख्या पचास गुनी से ज्यादा बढ़ गई है। झोंपड़ों के जरा से पुरवे विशाल नगर बन गये हैं। व्यावसायिक उन्नति की यह रफ्तार संसार के इतिहास में विस्मयजनक है। जहां जनता पर जनता के हित के लिए शासन किया जाता है, वहां ऐसी ही सफलता प्राप्त होती है। साम्राज्यवादी योरोप अभी तक यही नहीं तय कर पाया है कि फौजी सामान घटाया जाय या नहीं। उधर रूस एकाग्र भाव से उन्नति के मार्ग पर बढ़ता जा रहा है। न वहां बेकारी है, न मन्दी। (विविध प्रसंग, भाग 2, 28 नवम्बर 1932)

समाजवाद के स्पर्श से शिक्षा, आजादी, विज्ञान, साहित्य, खुशहाली, इन्सानियत से परिपूर्ण हो उठा था देश

नारायण गंगोपाध्याय

लेनिन, उसके बाद स्तालिन। बेरोकटोक चलने लगा पंचवर्षीय अग्र अभियान। शिक्षा से, आजादी से, विज्ञान से, साहित्य से, खुशहाली से, इन्सानियत से पूर्ण हो उठा था देश। यह कैसे होता कि देश में एक भी बेरोजगार नहीं रहे? यह कैसे सम्भव है कि वेश्यावृत्ति और भिक्षावृत्ति सुदूर इतिहास की विषयवस्तु बन जाए? अकाल और दुर्भिक्ष मुंह छुपा कर किस रास्ते से भाग जाये? आबादी की भरमार वाली पृथ्वी पर जब जनसंख्या नियंत्रण की बातें मनीषियों द्वारा की जा रही हों, तब कौन कह सकता है कि और भी आदमी चाहिएं–और भी काम करने वाले चाहिएं? हर आदमी कैसे देश और कौम के लिए जरूरी हो जाता है? कौन यकीन के साथ हर नर-नारी को सोच सकता है–देश की हर ईंच जमीन उनकी है, हर फसल के दाने-दाने पर उनका हक है? कैसे गायब हो जाता है धर्मों और सम्प्रदायों के बीच चिरन्तन दरिन्दगी भरा विद्वेष, इस्लाम और ईसायत के बीच सदियों से संचित विरोध?

किन्तु स्तालिन ने यह सब कुछ सचमुच साकार कर डाला था। लेनिन जिसकी बुनियाद रख गये थे, स्तालिन ने उस पर प्रगति और आजादी का अजेय दुर्ग निर्मित कर दिया था।

लेनिन ज़िन्दाबाद

बर्तोल्त ब्रेख्त

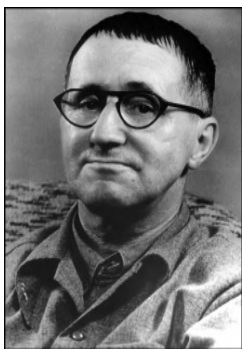

पहली जंग के दौरान
इटली की सानकार्लोर जेल की एक अन्धी कोठरी में
ठूँस दिया गया एक मुक्तियोद्धा को भी
शराबियों, चोरों और उचक्कों के साथ
खाली वक्त में वह दीवार पर पेंसिल घिसता रहा
लिखता रहा हर्फ़-ब-हर्फ़ –
लेनिन ज़िन्दाबाद !

ऊपरी हिस्से में दीवार के
अँधेरा होने की वज़ह से
नामुमकिन था कुछ भी देख पाना
तब भी चमक रहे थे वे अक्षर–बड़े-बड़े और सुडौल
जेल के अफसरान ने देखा
तो फौरन एक पुताईवाले को बुलवा
बाल्टी-भर क़लई से पुतवा दी वह ख़तरनाक इबारत
मगर सफ़ेदी चूँकि अक्षरों के ऊपर ही पोती गई थी
इस बार दीवार पर चमक उठे सफेद अक्षर :
लेनिन ज़िन्दाबाद !

तब एक और पुताईवाला लाया गया
बहुत मोटे ब्रश से, पूरी दीवार को
इस बार सफेदी-सुर्खी से वह पोतता रहा बार-बार
जब तक कि नीचे के अक्षर पूरी तरह छिप नहीं गए
मगर अगली सुबह
दीवार के सूखते ही, नीचे से फूट पड़े सुर्ख अक्षर–
लेनिन ज़िन्दाबाद !

तब जेल के अफसरान ने भेजा एक राजमिस्त्री
घंटे-भर तक वह उस पूरी इबारत को
करनी से दुरचता रहा सधे हाथों
लेकिन काम के पूरे होते ही
कोठरी की दीवार के ऊपरी हिस्से पर
और भी साफ नजर आने लगी
बेदार बेनजीर इबारत –
लेनिन ज़िन्दाबाद !

तब उस मुक्तियोद्धा ने कहा –
अब तुम पूरी दीवार ही उड़ा दो !

हरियाणा में जनसभा और विशाल जुलूस

(पृष्ठ 1 का शेष)

क्रान्ति के शताब्दी समारोह पर 7 नवम्बर को रोहतक में राज्य स्तरीय एक विशाल जुलूस निकाला। इसमें शामिल हजारों लोगों ने देश में बढ़ रही आर्थिक व सामाजिक गैरबराबरी और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी जोरदार आवाज बुलन्द की। जुलूस सेक्टर-1 के देवीलाल पार्क से दिल्ली बाईपास, विश्वविद्यालय, जाट कॉलेज, मेडिकल मोड़ व डी-पार्क होते हुए मॉडल टाउन के डबल पार्क तक निकाला गया। जुलूस बहुत ही भव्य, सुसज्जित, अनुशासित व उत्साहवर्धक था। सबसे आगे विश्व के 6 महान कम्युनिस्ट शिक्षकों के चित्र लिए स्वयंसेवक चल रहे थे। उनके पीछे दुनिया की पहली समाजवादी क्रान्ति के 100 सालों के प्रतीक के रूप में 100 लाल झण्डे लिए हुए स्वयंसेवक थे। इस दिन सुबह सवेरे से ही महान नवम्बर क्रान्ति के चित्रों व इसकी सीखों की प्रदर्शनी देवीलाल पार्क में लगाई गई थी जिसे लोगों ने पूरी तन्मयता से देखा व पढ़ा। प्रदेश भर से आये लोगों को वहां एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की केंद्रीय कमेटी के सदस्य एवं हरियाणा राज्य कमेटी

रोहतक : देवीलाल पार्क में आयोजित नवम्बर क्रान्ति के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कॉ. सत्यवान

के सचिव कॉ. सत्यवान और राज्य कमेटी सदस्य कॉ. अनूप सिंह ने सभा की अध्यक्षता की। कॉ. राजेन्द्र सिंह व कॉ. रामफल ने भी संबोधित किया। कॉ. सत्यवान ने कहा कि पिछले 5 सालों में महंगाई, बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ी है। इससे गरीबों की आमदनी घटी है, जबकि पूंजीपतियों की आमदनी तीन गुना बढ़ी है। इससे देश की 58 प्रतिशत धन-संपत्ति केवल एक प्रतिशत अमीरों के हाथ आ गई है। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार ने इस विषमता को बढ़ाने का कार्य बेशर्मी के साथ किया है। नोटबन्दी व जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को अडानी-अम्बानी जैसे बड़े पूंजीपतियों की मुट्ठी में जकड़ दिया है। किसान कर्जवान हैं। महिलाओं समेत किसी की भी सुरक्षा नहीं है। कुपोषण, आत्महत्या व अवसाद बढ़ रहा है। शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था एक तरफ लोगों को कंगाल और दूसरी तरफ पशु से भी बदतर हैवान बना रही है। इसकी ताबेदार भाजपा सरकार के पास लोगों को बहकाने के लिए जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं है। जीवन के असल सवालों से ध्यान भटकाने के लिए लोगों में परस्पर वैरभाव व कलह फैलाई जा रही है। ये असहनीय हालात बदलाव की मांग कर रहे हैं। सत्यवान ने कहा कि एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) का आज का यह विशाल जुलूस प्रदेश में बदलाव लाने का एक नया संदेश पहुंचाएगा। 100 साल पहले 7 नवंबर 1917 को इसी दिन रूस की महान समाजवादी क्रान्ति ने दुनिया

(शेष पृष्ठ 5 पर)

मोदी सरकार द्वारा किये जा रहे हमलों के विरोध में उठी आवाज

भिवानी (हरियाणा) : मोदी सरकार द्वारा जनता पर किये जा रहे हमलों के विरोध में 30 अक्तूबर को जन एकता, जन अधिकार आन्दोलन मंच के आह्वान पर विभिन्न संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला जो नेहरू पार्क से शुरू होकर घण्टाघर, सराय चौपटा होते हुए हांसी गेट पर पहुंचा। इससे पहले सभी संगठनों के कार्यकर्ता स्थानीय नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए।

भिवानी: साम्प्रदायिक हमलों के खिलाफ शहर में मशाल जुलूस निकालते हुए वामदलों के कार्यकर्ता

ए.आई.यू.टी.यू.सी. के जिला सचिव कॉ. धर्मवीर सिंह, किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव कॉ. रोहतास सिंह सैनी, ए.आई.डी.वाई.ओ. के जिला सचिव कॉ. संदीप मेहरा, सीआईटीयू की तरफ से कॉ. ओमप्रकाश, अखिल भारतीय किसान सभा से कॉ. जय प्रकाश, जनवादी महिला संगठन की तरफ से नीलम, एआईडीएफआई से अभिषेक शर्मा, दलित अधिकार मंच से चन्द्रभान, रिटार्यड कर्मचारी संघ से एस.के. सिंगला आदि ने सभा को सम्बोधित किया।

सभा की अध्यक्षता एआईयूटीयूसी की तरफ से कॉ. राजकुमार और सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से यादवीरेन्द्र ने संयुक्त रूप से की। संचालन सीआईटीयू के कॉ. अनिल कुमार ने किया।

वक्ताओं ने कहा कि 'अच्छे दिन' लाने का वादा करके सत्ता में आई केन्द्र की मोदी सरकार और राज्य की खट्टर सरकार जनविरोधी नीतियॉ लागू कर रही हैं जिनकी वजह से बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर बढ़ता कर्ज, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण-व्यापारीकरण बढ़ता जा रहा है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ हैं। प्रगतिशील, तर्कशील, पत्रकारों व बुद्धिजीवियों को विरोध में आवाज उठाने पर मौत के घाट उतारा जा रहा हैं तथाकथित गो-रक्षकों के द्वारा बेकसूर लोगों को पीट-पीटकर मारा जा रहा है। दलितों का सामाजिक उत्पीड़न हो रहा हैं। श्रम कानूनों में मजदूर-विराधी संशोधन करके पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। किसानों को फसल का लागत मूल्य से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने की सिफारिश करने वाली स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू न करके वादा खिलाफी की जा रही हैं।

वक्ताओं ने इन सब जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी प्रगतिशील, जनवादी, वामपंथी ताकतों को एकजुट होने और अपनी आवाज बुलंद करने का पुरजोर आह्वान किया। 9-10-11 नवम्बर 2017 को संसद के सामने होने वाले महापड़ाव को पूर्ण सर्मथन देते हुए इसे सफल करने का भी आह्वान किया गया।

सोनीपत : साम्प्रदायिक हमलों के खिलाफ शहर में मशाल जुलूस निकालते हुए वामदलों के कार्यकर्ता

उजाड़ी गई झुग्गी बस्ती के मजदूरों के पुनर्वास की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

गुरुग्राम (हरियाणा) : गरीब प्रवासी मजदूरों के 50 परिवारों के लगभग 200 लोग सिकन्दरपुर घोसी, नजदीक हनुमान मन्दिर, जी-ब्लाक, डीएलएफ, फेस-1, गुरुग्राम में झुग्गी डालकर पिछले 27 सालों से रह रहे हैं। ये भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में मेहनत-मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल-पोस रहे हैं। इस बस्ती से मजदूरों के लगभग 70 बेटा-बेटियाँ सातवीं से ग्यारहवीं कक्षा तक स्कूलों में पढ़ रही हैं। सभी मजदूर भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हरियाणा में पंजीकृत सदस्य हैं। इन मजदूरों की मजदूरी स्थाई नहीं है। कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं। मजदूरी निहायत कम मिलती है। ये लोग मकान किराये पर लेकर रहने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं। इनके आधार कार्ड हैं। इनके लिए आवासीय व्यवस्था करने की बजाय सरकार के द्वारा बार-बार प्रताड़ित किया जाता है। नगर निगम द्वारा घर के मुखिया एवं परिवारों की अनुपस्थिति में नाजायज और बेरहम तरीके से 7 नवम्बर के दिन ग्यारह बजे से तीन बजे तक जेसीबी चलाकर इनकी सारी बस्ती को तोड़ फोड़ दिया गया और इनका सामान तक नष्ट कर दिया गया। इतने सालों से यहाँ पर रहने वाले देश के ये नागरिक अपनी बहू-बेटियों समेत खुले आसमान के नीचे ठण्ड में तड़पने को मजबूर हैं जहां उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरों के लिए मकान बनाने वालों के सर पर छत नहीं है।

8 नवम्बर को भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा संबंधित एआईयूटीयूसी ने प्रशासन से मांग की कि इन बेघर गरीब मजदूर परिवारों के पुनर्वास की अति शीघ्र व्यवस्था की जाएं। ज्ञापन देने वालों में एआईयूटीयूसी के जिला सचिव कॉ. रामकुमार, जिला प्रधान ओमप्रकाश पासवान, उप प्रधान कोमल सिंह और भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के जिला सचिव हेमराज शामिल थे।

गुरुग्राम : निर्माण मजदूरों की ठूठी हुई झुग्गियां

साल गुजरने से पहले ही महज झांसा साबित हुई नोटबंदी

नोटबंदी को एक साल हो गया है। 8 नवम्बर, 2016 को इसकी बरसी है। 2016 में इसी दिन अचानक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी का एलान किया था। कहा था कि इससे काला धन बाहर निकलेगा, नकली नोट का चलन बंद हो जाएगा और आतंकवाद की फण्डिंग बंद हो जाएगी।

सौ से अधिक लोगों ने जान गंवाई, मानी हुई बात है कि बाजार को भारी नुकसान हुआ, लोगों को हुई परेशानियों के बदले में लम्बे अर्से से इन समस्याओं के समाधान की आशा में लोग मुखर थे। लेकिन भारत के तमाम लोगों को क्या मिला? पिछले साल नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था – 1) केवल 50 दिन का समय दे दो। इन 50 दिन तक कष्ट उठाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। 2) जापान यात्रा से लौट कर आते ही गोवा में कहा था कि 'अगर 50 दिन के बाद भी हालात नहीं सुधरे, तो देश के किसी भी चौराहे पर खड़ा करके मुझे जनता जो भी सजा दे सकती है। 3) मुरादाबाद में कहा था, 'ये जो एटीम और बैंक काउंटरों पर लाइनें लगी हुई हैं ये भारत में आखरी लाइनें हैं।' 30 दिसम्बर 2016 के बाद 'भारत में किसी मामले में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।' 4) गाजीपुर की सभा में कहा था, काला धन, जाली नोट, भ्रष्टाचार, घूसखोरी ये सब आगे नहीं रहेगा।'

प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करने से राशन, बैंक, ट्रेन टिकट काउंटर, डाकखाने, किसी भी सेवा के लिए अब लाइन नहीं लगानी चाहिए। देश से काला धन, जाली नोट, भ्रष्टाचार, बेइमानी, रिश्वतखोरी अन्तर्हित हो जाने की थी। 2017 का साल भारत को एक सही मायने में भ्रष्टाचार मुक्त श्रेष्ठ राष्ट्र में तब्दील कर देगा–यह थी लोगों की प्रत्याशा। यह कितनी पूरी हुई है?

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 99 प्रतिशत नोट बैंक के कोषागार में वापस जमा हो चुके हैं। क्या अब तक भी संबद्ध बैंकों में जमा नोटों की गिनती हुई नहीं है। विशेषज्ञों ने कहा था कि कुल काले धन का सिर्फ छह प्रतिशत ही नकदी के रूप में जमा रहता है। ऐसा हो तो बाकी 94 प्रतिशत काला धन, जो नकद जमा नहीं होता है, वह नोटबंदी से कैसे बरामद होगा? यह सवाल उन्हीं दिनों उठा था। वित्तमंत्री ने माना था कि आज तक कितना काला धन बरामद हुआ है, उसका कोई आंकड़ा मालूम नहीं है। बल्कि इस 'सुअवसर' पर काला धन रखने वाले कई मालिकों ने उसे सफेद कर लिया। इसके अलावा नये नोट जाली मिलने की मुंह बोलती मिसालें आज सभी के सामने हैं। देश के लोगों की जानकारी में यह नहीं है कि बहुत बड़ा छापा मारने का कोई सार्थक उपाय किया गया हो। ऐसा हुआ है तो नेट रिजल्ट जीरो ही नहीं, बल्कि माइनस पर पहुंच गया है।

2006 में स्वीस बैंक एसोसियेशन रिपोर्ट में बताया गया था कि स्वीस बैंक में भारतीय काले धन की मात्रा 1,48,600 करोड़ डालर है। यह मात्रा दूसरे-दूसरे सब देशों की कुल मिला कर जितनी अमानत है उससे ज्यादा है। यह देश के विदेशी कर्ज से 13 गुनी ज्यादा रकम है।

634 व्यक्तियों के विदेश में जमा काले धन की कुल मात्रा भारतीय धन-दौलत से दुगुनी है। यह काला धन क्या सरकार ने बरामद कर लिया है? बरामद करना तो दूर की बात, सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के कारोबारियों का नाम प्रकाशित करने को कहा था, सरकार उस पर भी राजी नहीं हुई। काला धन एक प्रक्रिया से पैदा होता है। यह प्रक्रिया बंद किये बिना नोटबंदी के जरिये काला धन रोका नहीं जा सकता। यह बात आज सच साबित हो गई है। साबित हो गया है कि काला धन पकड़ना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री का असल मकसद था अपनी सरकार की हर मोर्चे पर हो रही नाकामी और कुशासन से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ फेरने के लिए जुमलेबाजी करना।

काला धन बरामद करना ही अगर सरकार का असल मकसद होता तो काले धन के बड़े-बड़े बागड़ बिलों में से एक को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इस सवाल पर पहले वाली सरकार और बीजेपी सरकार में क्या कोई भी फर्क है? 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करके नये नोट छापने में बड़ा भारी पैसा जाया हुआ, केन्द्र और राज्य सरकारों को राजस्व का बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा, लोगों को बेहद परेशानी झेलनी पड़ी, सौ से ज्यादा लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा लेकिन इन सबके बदले में देश के लोगों को क्या मिला? राष्ट्रीयकृत बैंकों से लगभग 8 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेकर चुका नहीं रहे रिलायंस वाले अनिल अम्बानी, वेदांत समूह के अनिल अग्रवाल, एस आर ग्रुप के शशि रूइया-रुबी रुइया, अडाणी समूह के गौतम अडाणी, विजय माल्या, ललित मोदी जैसे और भी कई धनकुबेर। सरकार उन्हें गिरफ्तार करके उनकी सम्पत्ति जब्त क्यों नहीं कर लेती? यह सब देख कर क्या कोई मान सकता है कि सरकार कर्ज न चुकाने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ है? सरकार के एक पर एक कदमों से यह साफ जाहिर है कि सरकार कतई नहीं चाहती कि काला धन बरामद किया जाए और बैंकों का पैसा मारे बैठे धन्नासेठों से कर्ज वसूल किया जाये। इन सब बागड़ बिल्लों से कर्ज वसूलना तो दूर की बात, ताकि वे फिर कर्ज ले सकें, इसके लिए सरकार डूबते जा रहे बैंकों से और भी 2.11 लाख करोड़ रुपया मूलधन के तौर पर जुटा रही है। यह रुपया तो जनता का ही धन है। सरकार वही रुपया नये सिरे से ढाल रही है। जबकि देश के किसान कर्ज न चुका पाने से आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार से कर्ज माफी की मांग किये जाने पर लाठी-गोली खाकर जान गवां रहे हैं।

यह भ्रष्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हर पल काले धन को जन्म देती जा रही है। इस आर्थिक व्यवस्था को टिकाये रखने वाली और उसके रख-रखाव के तमाम इन्तजाम करने वाली किसी भी सरकार के लिए काला धन खत्म करना मुमकिन नहीं है। काले धन के खिलाफ बीजेपी का नारा इसलिए एक राजनैतिक जुमले के सिवा और कुछ नहीं है।

महान नवम्बर क्रान्ति के 100 साल ...

(पृष्ठ 4 का शेष)

में बदलाव का एक संदेश दिया था। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने अपने संस्थापक महान मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष के क्रांतिकारी विचारों की रोशनी में गत पूरे साल महान नवम्बर क्रान्ति की सीखों को हर गांव शहर पंहुचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाये हैं। इस कार्यक्रम का समापन समारोह आगामी 17 नवंबर को कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में होगा। जुलूस की अगुवाई पार्टी की राज्य कमेटी के सदस्य अनूप सिंह मातनहेल, राजेन्द्र सिंह, रामफल, ईश्वर सिंह राठी, जयकरण, रोशन लाल, मेहर सिंह, हरिप्रकाश, विजयकुमार, बलवान सिंह आदि ने की।

चंडीगढ़ : महान नवम्बर समाजवादी क्रांति के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 11 नवम्बर को सरकारी संग्रहालय और आर्ट गैलरी के सभागार में एक जनसभा हुई। इसकी अध्यक्षता डा. जगदीश चंद्र ने की। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड सत्यवान मुख्य वक्ता थे। कॉ. ईश्वर सिंह राठी, कॉ. थाना सिंह, दीपक कुमार ने भी सभा को सम्बोधित किया। कॉ. बाबूराम और कॉ. रोशनलाल, इंदर सिंह और कॉ. शिवाशीष प्रहराज भी सभा में उपस्थित रहे।

चण्डीगढ़ : महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष पर आयोजित जनसभा में भाग लेते हुए लोग

महान नवम्बर मजदूर क्रांति की शताब्दी पर परिचर्चा

नई दिल्ली : महान नवम्बर मजदूर क्रांति की शताब्दी पर 29 अक्टूबर को एआईयूटीयूसी से सम्बन्धित दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिऐशन (दावा) यूनियन के द्वारा 'समाज के इतिहास में नारियों की स्थिति व भूमिका तथा नारी उत्थान में नवम्बर क्रांति की भूमिका' विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में एसयूसीआई (सी) दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. प्राण शर्मा ने अपनी चर्चा में कहा कि बहुत दिनों से समाज में भाववाद व वस्तुवाद के दो चिंतन काम करते आ रहे हैं। हमें वस्तुवादी ढंग से विचार करना चाहिए। वस्तुवादी ढंग से विचार नहीं करने से हम सामाजिक समस्याओं के बारे में सही समझ नहीं बना सकते हैं। परिचर्चा के विषय पर एआईयूटीयूसी के दिल्ली राज्य अध्यक्ष का हरीश त्यागी ने भी अपनी बात रखी। परिचर्चा की अध्यक्षता एआईयूटीयूसी के दिल्ली राज्य सचिव और आशा यूनियन के अध्यक्ष का एम चौरसिया ने की। दावा यूनियन की कार्यकारी अध्यक्ष सोनू, कार्यालय सचिव कविता सिंह, सुजाता व कई अन्य ने परिचर्चा में हिस्सा लिया। एलएचवी और एएनएम स्टाफ यूनियन से शकुंतला ने भी अपनी बात रखी। परिचर्चा में बड़ी संख्या में आशा वर्कर शामिल हुई।

दिल्ली: परिचर्चा में भाग लेती हुई आशा कार्यकर्ता

अपने भाषण में कॉ. सत्यवान ने कहा कि नवम्बर क्रांति होने के बाद से इस दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इसके बाद सौ साल बीत चुके हैं। दुनिया भर में लोग इस ऐतिहासिक घटना की शताब्दी का जश्न मना रहे हैं। प्रमुख मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारकों में से कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा स्थापित देश की एकमात्र सही कम्युनिस्ट पार्टी एसयूसीआई (सी) महान नवम्बर समाजवादी क्रांति के 100 साल पूरे होने पर एक वर्षीय कार्यक्रम के माध्यम से सबसे उपयुक्त तरीके से यह समारोह मना रही है। यह महान नवंबर क्रांति की शिक्षाएं याद करने और आत्मसात करने का एक प्रयास है। इसने यह सीख एक बार फिर सामने ला दी है कि यह शोषणकारी व्यवस्था पूंजीवाद सभ्यता की प्रगति और मानव जाति के चहुंमुखी विकास में बाधक है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद ही वह दर्शन है जो मानव द्वारा मानव के शोषण से मुक्ति की राह रोशन करता है। इसके साथ ही नवंबर क्रांति शताब्दी समारोह ने एक बार फिर संशोधनवाद आदि मुद्दों को सामने लाया दिया है। यह दिखाया कि यह कैसे आता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और सामाजिक स्वार्थ के साथ व्यक्तिगत स्वार्थ को एकात्म कर क्रांतिकारियों को समाजवादी व्यक्तिवाद और नव अर्थवाद के खिलाफ कैसे लड़ना है।

महान नवम्बर क्रांति की शिक्षाओं को दोहराते हुए कॉ. सत्यवान ने हर प्रकार के शोषण से लोगों की मुक्ति के लिए देश में पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति के परिपूरक जोरदार आंदोलन गठित करने का आग्रह किया। इंटरनेशनल गान के साथ सभा समाप्त हुई।

लखनऊ (उ.प्र.) : 29 अक्टूबर को सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के तत्वावधान में महान नवम्बर क्रांति शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक जनसभा का आयोजन राज्य की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद स्थित गंगा प्रसाद वर्मा मेमोरियल हाल में किया गया। जनसभा की अध्यक्षता पार्टी के राज्य सचिव कॉ. पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा ने की और संचालन राज्य कमेटी के

(शेष पृष्ठ 7 पर)

6 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

सर्वहारा दृष्टिकोण

22 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2017

बेरोजगारी के खिलाफ कन्वेन्शन

रायपुर छ.ग.) : आउटसोर्सिंग बन्द करने, ठेकेदारी प्रथा व निजीकरण बन्द करने, युवाओं को सही रोजगार देने, रोजगार नहीं मिलने तक सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता देने, सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को तत्काल भरने, न्यूनतम वेतन 18000 रु. देने व इसे सभी प्राइवेट संस्थानों स्कूल-कॉलेजों, हस्पतालों व उद्योगों में लागू करने, प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस आधी करने, भर्ती व प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस अधिकतम 50 रु. करने आदि मांगों को लेकर 8 अक्टूबर को युवा संगठन ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (ए.आई.डी.वाई.ओ.) छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा रायपुर, मठपारा दुर्गा चौक पर राज्य स्तरीय युवा कन्वेन्शन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार प्रभाकर चौबे, अतिथि डीवाईओ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कॉ. मानस पाल व कॉ. समीक्षा पांडे एवं मुख्य वक्ता के रुप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ. विश्वजीत हारोडे उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने युवाओं की वर्तमान समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज युवा सबसे ज्यादा परेशान है और तमाम सरकारों की लगातार युवा-विरोधी नीतियों ने इसे और भयावह बना दिया है। सभी ने तमाम समस्याओं के खिलाफ जोरदार युवा आंदोलन निर्मित करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन आत्माराम साहू एवं देवेन्द्र पाटिल ने किया।

रायपुर (छ.ग.) : बेरोजगारी के खिलाफ कन्वेन्शन में भाग लेते हुए युवक-युवतियां

भोपाल में छात्रा से हुए वीभत्स सामूहिक बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

एक नवंबर को भोपाल में एक 19 वर्षीय पीएससी की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के खिलाफ गत दिनों ऑल इण्डिया डीएसओ और ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से चेतक ब्रिज पर जोरदार नारों के साथ एक विरोध प्रदर्शन किया गया। वहां हुई विरोध सभा का संचालन ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की जिला सचिव आरती शर्मा ने किया। संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती रितु श्रीवास्तव ने कहा कि जब पुलिस की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी है। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती जोली सरकार ने भोपाल मे पीएससी की छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना की निंदा करते हुये बलात्कारियों को उदाहरणमूलक सजा देने और मध्य प्रदेश मे पूर्ण शराबबंदी लागू करने की माँग की। साथ ही उन्होने आम जनता से अपील की कि महिलाओं और बच्चियों पर लगातार बढ़ते अपराधों के खिलाफ एकजुट होकर जोरदार जन आन्दोलन गठित करें।

गुना में भी ऑल इण्डिया डीएसओ और ऑल इण्डिया एमएसएस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।

निर्माण कारीगर-मजदूरों ने अपनी मांगों पर उपायुक्त कार्यालय पर दिया धरना

भिवानी(हरियाणा) : अपनी ज्वलंत मांगों के लिए शहर में प्रदर्शन करते हुए भवन निर्माण कारीगर-मजदूर

भिवानी (हरियाणा) : 2 नवम्बर को भवन निर्माण कारीगर-मजदूरों की यूनियनों ने संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया और जिला उपायुक्त भिवानी की मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेने आये तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि निर्माण श्रमिकों की सुनवाई की जाएगी।

धरने की अध्यक्षता संयुक्त रूप से भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा संबन्धित एआईयूटीयूसी की तरफ से कॉमरेड राजकुमार जांगड़ा, भवन निर्माण मजदूर संघ हरियाणा संबन्धित एटक से सुरेश कुमार, भवन निर्माण श्रमिक विकास संगठन हरियाणा संबंधित एचएमएस से सुरजभान, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा संबंधित सीटू से कॉ. जयभगवान, भवन निर्माण वं सन्निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा संबंधित एंटक से शकुन्तला और भवन कामगार यूनियन संबंधित इंटक से विजय ने की।

भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा से कॉमरेड धर्मवीर सिंह, भवन निर्माण मजदूर संघ हरियाणा से रामअवतार खोरड़ा, भवन निर्माण श्रमिक विकास संगठन हरियाणा से रतन लोहिया, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा से कॉ. अनिल कुमार, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा से फूलसिंह और भवन कामगार यूनियन से सतबीर ने धरने को सम्बोधित किया। धरने का संचालन भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा से मनोहर लाल ने किया।

वक्ताओं ने बताया कि भवन निर्माण मजदूरों को बेवजह कागजी कार्यवाही में धकेल कर परेशान किया जा रहा है। मजदूर की आईडी में नाम के मामूली से अन्तर पर फार्म को रद्द कर दिया जाता है, जबकि इससे पहले नाम में अन्तर पर हल्फनामा देने का प्रावधान था। इसके अलावा पंजीकृत कापी के नवीनीकरण और हितलाभ फार्मों को जमा करवाने के लिए मजदूर को स्वयं हाजिर होने का तुगलकी फरमान बोर्ड ला रहा है, जिसका सभी यूनियनें जोरदार विरोध करती हैं। दिहाड़ी छोड़कर मजदूरों के स्वयं हाजिर होने से किराये-भाड़े और अलग से व्यक्तिगत बैंक ड्राफ्ट बनवाने पर 1000 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च उन पर आ जायेगा। दूसरी ओर, भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का न तो आधारभूत ढांचा है, न ही पर्याप्त संख्या में स्टाफ, जिससे इस बात की कोई गारन्टी नहीं की मजदूर के स्वयं हाजिर होने पर उसका काम हो पायेगा। दो-दो, तीन-तीन साल पहले जमा करवाये गये हितलाभ के लिए आवेदनों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। समय-समय पर आपके द्वारा की गयी घोषणायें भी बोर्ड द्वारा लागू नहीं की गयी हैं। बोर्ड द्वारा बेरुखी भरा यह रवैया कामगारों में विक्षोभ पैदा कर रहा है।

अध्यक्षीय भाषण में भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा संबंधित एआईयूटीयूसी के कॉमरेड राजकुमार जांगड़ा ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं कि भवन निर्माण कामगारों का सामाजिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। इनके लगातार श्रमदान से ही युग-युग से मकान, शहर-नगर, हस्पताल, कार्यालय, स्कूल-कॉलेज व विश्वविद्यालय आदि के भवन बने हैं। सभ्यता का निर्माण हुआ है। इन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता, सुविधाएं, हितलाभ और पूरी मान-मर्यादा दी जानी चाहिए। लेकिन 1996 में कानून बन जाने के बाद भी घोषित लक्ष्य से अभी कोसों दूर हैं। भवन निर्माण मजदूर-कारीगरों के कल्याण बोर्ड के पास करोड़ों रुपये जमा पड़े हैं लेकिन कारीगर-मजदूरों के कल्याण हेतु निहायत ही कम पैसा वितरित किया जाता है। दरअसल किसी भी मजदूर को दुर्घटना में घायल होने या जटिल बीमारी आदि में मेडिकल के नाम पर कोई सहायता नहीं दी जाती है। न पेंशन दी जाती है और न ही विकलांग बच्चों की परवरिश हेतु आवेदन फार्म जमा किये जाते हैं। अधिकतर कामगारों के पास खुद का घर नहीं है और जिनके पास घर है उसकी हालत खस्ता है, लेकिन मकान बनाने के लिए सहायता का आज तक आवेदन फार्म भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। कन्यादान हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी तरह-तरह की शर्तें लगायी जा रही हैं। यह नाजायज मार बीपीएल परिवारों पर पड़ रही है। उन्हें समाज कल्याण विभाग से एनओसी लाने तक पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसी ही अड़चनें छात्रवृत्ति सहायता में लगायी जा रही हैं। अधिकारी इन सब नयी-नयी शर्तों का नोटिफिकेशन तक नहीं दिखाते।

ज्ञापन में निम्न मांग की गयी: 1. भिवानी-दादरी में स्थाई सहायक निदेशक की नियुक्ति की जाए। 2. पंजीकरण, नवीनीकरण व सुविधा फार्म जमा करवाने के लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष सुविधा की जाए। 3. सुविधाओं में की गयी कटौती को वापिस लिया जाए। 4. हित लाभ आवेदन फार्मों को जमा करवाने में मामूली नामों में अन्तर पर हल्फनामा देने का प्रावधान लागू किया जाये। 5. अंशदान और हितलाभ आवेदन फार्म जमा करवाने में मजदूर को हाजिर होने की शर्त हटाकर पहले की तरह यूनियनों को मजदूरो की कॉपी का नवीनीकरण कराने व हितलाभ आवेदन फार्म जमा करवाने का अधिकार बरकरार रखा जाए। 6. डेढ़-दो साल पहले जमा कराये गये हित लाभ आवेदन फार्मों के पैसे तुरन्त मजदूरों के बैंक खातों में डाले जायें। 7. पिछले सत्र (2016-17)के छात्रवृत्ति के फार्मों के पैसों का भुगतान शीघ्र हो। 8. वर्तमान सत्र (2017-18) के छात्रवृत्ति फार्म का फॉर्मेट तुरन्त दिया जाये और फार्म को जमा करवाने की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च तक की जाये। और सभी पंजीकृत मजदूरों की छात्रवृत्ति लाभ पाने का हक हो।

दिल्ली सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर एस्मा लगाने की निंदा

3 नवम्बर 2017 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर कर्मचारी-विरोधी एस्मा कानून लागू कर दिया है। दिल्ली सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए ए.आई.यू.टी.यू.सी. की दिल्ली राज्य कमेटी के अध्यक्ष व कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ यूनियन, दिल्ली के सलाहकार कॉ. हरीश त्यागी ने कहा कि यह दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारियों की जायज आवाज को दबाने का घोर अलोकतांत्रिक कदम है, हम इसको लागू करने की निंदा करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल की उपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग व दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मिलित रूप में एस्मा लगाने का निर्णय किया गया जोकि कानून व शक्तियों का घोर दुरुपयोग है। यह बात प्रकाश में आई है कि यह निर्णय कैट्स एम्बुलेंस के आऊटसोर्स कर्मचारियों की 3 दिनों से जारी हड़ताल के मद्देनजर किया गया है। जो भी हो इस निर्णय से स्वास्थ्य विभाग व कैट्स एम्बुलेंस के आऊटसोर्स कर्मचारियों के हितों व अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। कर्मचारी विरोधी यह निर्णय बीवीजी एण्ड यूकेएसएएस ईएमएस प्रा. लि. नामक निजी कम्पनी की एकतरफा सलाह व उसकी इच्छा के अनुरूप लिया गया है। इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि कैट्स एम्बुलेंस के संचालन को देखने व आऊटसोर्स कर्मचारियों को देखने वाली जो कम्पनी खुलेआम सभी कानूनों का उल्लंघन कर रही है उस कम्पनी के हित में दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारी लगे हुए हैं।

दिल्ली की कैट्स एम्बुलेंस सर्विसेज पर एस्मा लगाने के लिए कैट्स में कार्यरत कॉन्ट्रेक्ट के कर्मचारी के आंदोलन को प्रमुख कारण दिखाया गया है। इस निर्णय में इस बात की पूरी तरह से अनदेखी की गई है कि कैट्स सेवा में कार्यरत सैकड़ों कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारी पिछले दो साल से श्रम कानूनों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कानून के अनुसार वेतन, छुट्टियाँ , ईएसआई व ईपीएफ की सुविधाएं दी जायें और कम्पनी की तानाशाही व उसके अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के साथ किये जाने वाले गंदे व भद्दे व्यवहार को रोका जाए। मगर ऊपर से नीचे तक किये गए सभी प्रयास विफल हो गए। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अन्त में केंद्रीय मजदूर संगठन ए.आई.यू.टी.यू.सी. के नेतृत्व में कैट्स के कॉंट्रेक्ट कर्मचारियों ने आंदोलन का निर्णय लिया। हर सम्भव स्तर पर दस्तक दी गई मगर कुछ नहीं हुआ। अन्ततः हड़ताल का निर्णय करना पड़ा। श्रम दफ्तर की मध्यस्थता में कम्पनी व सरकार ने समझौता किया मगर समझौता लागू करने की बजाय, कानूनों का पालन करने की बजाय कम्पनी ने कर्मचारियों के कई नेताओं को नौकरी से हटाने का प्रयास किया। कॉंट्रेक्ट के कुछ कर्मचारियों को हटाने के भी आदेश जारी किये गए। फलतः पुनः कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री की मध्यस्थता में हुई मीटिंग में यह निर्णय वापस लिया गया और कानून लागू करने का वचन दिया गया। मगर कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ। कैट्स प्रशासन व कंपनी ने कर्मचारियों के लिए कुछ करने की बजाय एक कर्मचारी नेता को कार्यालय में बुलाकर उससे दुर्व्यवहार किया और उस पर कुछ आरोप लगाकर पुलिस को सौंप दिया। इससे कर्मचारी गुस्सा हो गये और नेता के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ व उस पर लगाये गये केस वापस लेने की मांग पर वे हड़ताल पर चले गए। इस बार फिर से कर्मचारियों के पास हड़ताल करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा। इसकी आड़ में समस्त स्वास्थ्य क्षेत्र पर एस्मा लागू कर दिया गया। यह साफ है कि एस्मा लागू करने की भी कोई वास्तविक व कानूनी स्थिति नहीं थी। अतः एस्मा लगाना एक साजिशाना कार्यवाही है जिसके पीछे स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरते कर्मचारी आंदोलनों को दबाना है। यहाँ यह देखने की बात है कि इस कर्मचारी-विरोधी निर्णय में दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल एक साथ हैं जो बहुत बार एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं।

यह बात तब और भी साफ हो गई जब कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करते हुए पूरे प्रशासन ने कम्पनी के सुर में सुर मिला कर एम्बुलेंस सेवा पर एस्मा थोपने का काम किया। साथ ही कई कर्मचारियों को विभिन्न झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। सैकड़ों कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी कर दिया। बीवीजी एण्ड यूकेएसएएस ईएमएस प्रा. लि. नामक जिस कम्पनी के पास श्रम विभाग का ठेकेदारी का लाइसेंस नहीं है, उसी कम्पनी को दिल्ली सरकार के प्रशासन ने कैट्स एम्बुलेंस में ठेका दिया है और अभी यह कम्पनी अपने कॉन्ट्रेक्ट के नियमों का भी पालन नहीं कर रही है। फिर भी प्रशासन उसकी ही मदद में खड़ा है। अतः ए.आई.यू.टी.यू.सी. की दिल्ली राज्य कमेटी की तरफ से हम दिल्ली प्रशासन की भ्रष्ट भूमिका व कैट्स सहित स्वास्थ्य सेवा पर एस्मा लगाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि एस्मा तुरन्त हटाया जाए, कैट्स एम्बुलेंस से निकले गए सभी ठेका कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाए, गिरफ्तार किए गये सभी कर्मचारियों पर से केस वापस लेकर उनको रिहा किया जाए और कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ यूनियन के साथ बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों की सभी समस्याओं का कानूनसम्मत समाधान किया जाए।

सिविल हस्पताल अहमदाबाद में बच्चों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन

अहमदाबाद (गुजरात) : सिविल हस्पताल, अहमदाबाद में महामारी और बच्चों की मौत रोकने में गुजरात सरकार की विफलता और उसकी जिम्मेदारी तय करने में असफलता के खिलाफ 30 अक्टूबर को एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) ने एक प्रदर्शन किया। इसके अलावा, सीएजी रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है जो यह साबित करता है कि यह घटना हिमशैल का सिर्फ पानी से ऊपर दिखाई देने वाला सिरा मात्र ही है।

प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा निष्पक्ष जांच और इस घटना के लिए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की।

एचटेट की फीस बढ़ोतरी का एआईडीएसओ ने किया विरोध

रोहतकः 3 नवंबर 2017 को क्रांतिकारी छात्र संगठन आल इंडिया डीएसओ के प्रदेश सचिव हरीश कुमार सैनी ने खट्टर सरकार द्वारा एचटेट की फीस में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी को छात्र विरोधी व जनविरोध ी कदम बताया है।

उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकारें लगातार शिक्षा का निजीकरण करके इसे महंगा करती जा रही है। इससे लगातार शिक्षा के दरवाजे आम छात्रों के लिए बंद होते जा रहे हैं। जैसे-तैसे कुछ छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते है, उसके बाद सिर्फ नौकरी की लाइन में लगने के लिए तरह-तरह के टेस्ट व उन टेस्टों की भारी भरकम फीस होती है। जो कि गलत है। खट्टर सरकार ने एचटेट की फीस 67 फीसदी बढ़ा कर छात्रों पर एक और कुठाराघात किया है। प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है, नौकरी की कोई गारन्टी नही है। स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं। शिक्षा का बुरा हाल है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार तुरंत एचटेट की बढ़ाई गई फीस वापस ले, वरना इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा।

महान नवम्बर क्रान्ति के 100 साल ...

(पृष्ठ 5 का शेष)

वरिष्ठ सदस्य कॉ. जगन्नाथ वर्मा ने किया। कार्यक्रम में महान नवम्बर क्रांति के महत्व व प्रासंगिकता पर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सत्यवान ने कहा कि महान नवम्बर क्रांति मानव जाति की मुक्ति के इतिहास में अत्यंत गौरवमय घटना है। कॉ. लेनिन के नेतृत्व में रूस के मजदूर-किसानों ने उन दिनों साबित कर दिया था कि अगर आदर्श ठीक हो, नीति-सिद्धांत ठीक हों, तो सही क्रांतिकारी पार्टी के नेतत्व में मजदूर-किसान अनहोनी को होनी कर सकते हैं, पूँजीपतियों के हमले को नाकाम कर तमाम शोषण-उत्पीड़न का सदा के लिए खात्मा कर सकते हैं, सर्वहारा का अधिनायकत्व, समाजवाद कायम कर सकते हैं। मार्क्सवाद-लेनिनवाद का अनुसरण करते हुए मानव सभ्यता की बेजोड़ क्रांति सफल हुई और उससे भटकने पर ही इस समाजवादी व्यवस्था का पतन भी हो गया। यह तथ्य निर्विवाद रूप से मार्क्सवाद की अपराजेयता को साबित करता है।

अन्य वक्ताओं में राज्य कमेटी सदस्य कॉ. विजयपाल सिंह व कॉ. रविशंकर मौर्य ने महान नवम्बर क्रांति के संदर्भ में अपनी चर्चा में दिखाया कि मजदूर वर्ग की क्रांति व समाजवाद को जो धक्का लगा है, वह स्थायी नहीं है, सामाजिक तौर पर परिवर्तनकारी क्रांति अवश्यम्भावी है और समाज परिवर्तन का नियम भी यही है।

अध्यक्षीय सम्बोधन में पार्टी राज्य सचिव कॉ. पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा ने महान मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉ. शिवदास घोष के विचारों की रोशनी में आज के वामपंथी आन्दोलनों को सशक्त करने के लिए एक सही क्रांतिकारी पार्टी के रूप में एसयूसीआई(सी) की महती भूमिका पर प्रकाश डाला और इसे ताकतवर बनाने की अपील की।

जयपुर (राजस्थान) : 8 नवम्बर को सांगानेर (जयपुर) में रूस की महान नवम्बर क्रांति शताब्दी वर्ष समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न इलाकों, गांवों, शहरों से बड़ी तादाद में आये मजदूर-किसानों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं आदि ने शिरकत की। सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड लेनिन पर रचित गीत गुनगुन ने गया। बाद में कॉ. कुलदीप व साथियों ने कई क्रांतिकारी गीतों की प्रस्तुती दी।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता केन्द्रीय कमेटी सदस्य व हरियाणा राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड सत्यवान ने महान नवम्बर क्रांति के ऐतिहासिक महत्व व वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता पर विस्तार से वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि आप आज से सौ साल पहले रूस के जो हालात क्रांति से पूर्व और बाद में जानकर

(शेष पृष्ठ 8 पर)

लखनऊ : सभा को संबोधित करते हुए कॉ. सत्यवान

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Publication :November 20, 2017

जीएसटी के खिलाफ की आवाज बुलंद

मुरादाबाद (उ.प्र.) : जीएसटी के खिलाफ शहर में हड़ताल व प्रदर्शन करते हुए पीतल कारीगर

मुरादाबाद (उ.प्र.) : पीतल नगरी मुरादाबाद में जीएसटी के खिलाफ 31 अक्तूबर को सफल हड़ताल हुई। पहले पीतल के कच्चे माल पर ही टैक्स लगता था। लेकिन अब उत्पादन के हर स्तर पर 18 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत तक जीएसटी लगा दिया गया है जिससे 'कारखानेदारों' और कारीगरों में भारी रोष व्याप्त है। जीएसटी के खिलाफ आन्दोलन गठित करने के लिए एआईयूटीयूसी की पहल पर कारीगरों की अनेक सभाएं की गई। जीएसटी-विरोधी मोर्चा नामक जन कमेटी गठित की गई। इसके आह्वान पर एक दिन की मुकम्मल हड़ताल हुई। ईदगाह मैदान में सभा हुई। इसमें मुख्य वक्ता झारखण्ड से आये कॉ. सुमीत राय ने बात रखी। सभा का संचालन एआईयूटीयूसी के उ.प्र. राज्य सचिव कॉ. विजयपाल ने किया। सभा की अध्यक्षता हाजी मुखत्यार ने की। सभा को हाजी अशरफ, हाजी तनवीर, किफायतउल्ला खां, अशलम ने भी सम्बोधित किया।

सभा के बाद विरोध प्रदर्शन भी किया गया। जुलूस जिला मैजिस्ट्रेट मुरादाबाद के कार्यालय तक गया। वहां चेयरमैन एवं सक्रेटरी, जीएसटी काऊन्सिल नई दिल्ली और उ.प्र. के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गये।

राजस्थान बीजेपी सरकार के अलोकतांत्रिक अध्यादेश की एसयूसीआई(सी) ने की निन्दा

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 22 अक्तूबर को जारी एक बयान में कहा कि राजस्थान में बीजेपी-नीत सरकार ने 'क्रिमिनल लॉ (राजस्थान एमेण्डमेंट) आर्डिनेन्स, 2017' नामक जो घोर अलोकतांत्रिक बिल विधानसभा में पेश किया है, हम उसकी तीव्र निन्दा करते हैं। इस बिल के मुताबिक भ्रष्टाचार में अभियुक्त कार्यरत या पूर्व न्यायधीशों, मैजिस्ट्रेटों या अफसरों का नाम प्रकाशित करना दण्डनीय अपराध होगा–अदालत से उनके नाम पर केश दर्ज कराने की इजाजत पाना तो दूर की बात रही।

यह कदम न केवल जनता के सच्चाई जानने के अधिकार का हनन करेगा, बल्कि यह प्रचार माध्यमों की आजादी पर भी सरासर चोट है। साथ-साथ, न्यायपालिका सहित सरकारी अफसरशाही को पूंजीवादी सरकार और सत्तारूढ़ बुर्जुआ राजनैतिक पार्टियों का अंधभक्त बनाने की खतरनाक साजिश है। नतीजतन निरंकुश सरकार की खुशामंद करने की बढ़चढ़ कर लालसा में वे उनकी तमाम मर्जियों और फरमानों को चुपचाप मान लेंगे और इस तरह पूरी सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था ही दरअसल मखौल बन कर रह जाएगी। राजस्थान सरकार का यह कदम–ताबेदार सरकार के जरिये बुर्जुआ राज्य के हाथों में धीरे-धीरे स्वेच्छाचारी राजनैतिक शक्तियां केन्द्रीकृत करना है और सरकार के गैरकानूनी कुकर्मों पर पर्दा डालना है जो साम्राज्यवादी- पूंजीवादी दुनिया में सर्वव्याप्त हैं–साफ जाहिर है कि यह प्रशासनिक फासीवाद की शुरूआत है। साम्राज्यवाद- पूंजीवाद आज न केवल भ्रष्टाचार और विभिन्न गैरकानूनी काले कारनामों को जन्म दे रहा है, बल्कि इनके सहारे ही यह व्यवस्था खड़ी है। इन सब पर पर्दा डालने के लिए नित नई-नई साजिशों का सहारा लिया जा रहा है ताकि लोकतंत्र का गला घोंट कर राज्य के हाथों में चरम शक्ति प्रदान करके लोकतंत्र के लबादे की आड़ में फासीवाद कायम किया जा सके।

इसलिए एकजुट जोरदार जन आन्दोलन के जरिये सरकार को यह काला अध्यादेश वापस लेने के लिए मजबूर नहीं किया गया तो पूरे देश को ही धीरे-धीरे फासीवाद की तरफ धकेल देना हो जाएगा। इसलिए, केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के मेहनतकश लोगों से हम अपील करते हैं कि सरकार के इस कदम का जोरदार प्रतिवाद करते हुए पूरा जोर लगा कर उपयुक्त आन्दोलन गठित कर शासक पूंजीपति वर्ग और इसकी ताबेदार सरकार की इस घिनौनी साजिश को नाकाम करें।

नोटबंदी की बरसी पर दिल्ली में वामदलों का विरोध प्रदर्शन

6 वामपंथी पार्टियों ने विनाशकारी नोटबंदी की पहली बरसी पर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया था। इसी कड़ी में 8 नवम्बर, 2017 को दिल्ली में वामपंथी पार्टियों सीपीएम, सीपीआई, एसयूसीआई(कम्युनिस्ट), सीपीआई(एमएल), फार्वर्डब्लाक, आरएसपी तथा सीजीपीआई ने मंडी हाऊस से संसद मार्ग तक विरोध मार्च किया। जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिये जाने पर संसद मार्ग पर हुई विरोध सभा को अन्य वामपंथी पार्टियों के नेताओं के अलावा एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्राण शर्मा ने भी संबोधित किया।

सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड प्राण शर्मा

नोटबंदी की मुसीबत के ऐलान का एक साल पूरा होने पर देशव्यापी प्रतिवाद का आह्वान

गत वर्ष 8 नवम्बर की शाम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपये के नोट चलन से बाहर करने के फैसले का एलान करके देश के करोड़ों करोड़ आम आदमियों की जिन्दगी में घोर बदहाली ला दी थी। 100 से ज्यादा लोगों का मारा जाना, लाखों लाख लोगों का रोजगार से हाथ धो बैठना, बेहद परेशानी ही नहीं हुई बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का जो नुकसान हुआ है, उससे लगे धक्के से सम्भलने में और कितने दिन लगेंगे यह कोई नहीं बता पा रहा है। इन हालात में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) सहित 6 वाम दलों ने आगामी 8 नवम्बर को इस विनाशकारी फैसले का एक साल पूरा होने के दिन देशव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाने का आह्वान किया है।

25 अक्तूबर को इन पार्टियों के संयुक्त बयान में केन्द्र की बीजेपी सरकार जिस तरह देश में धार्मिक आधार पर फूट डाल रही है और साम्प्रदायिकता फैला रही है उसके खिलाफ डटकर खड़े होने के लिए इन 6 वामपंथी पार्टियों ने देश के तमाम लोगों से अपील है।

वामदलों के नेताओं ने इस बयान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किसान आन्दोलन के प्रति एकजुटता का इजहार किया। बेघर रोहिंगाओं को शरणार्थियों के रूप में मान्यता देने और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई।

महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी समारोह

(पृष्ठ 7 का शेष)

अचम्भे में पड़ जाओगे। रूस जहां गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महामारी आदि से ग्रस्त था। अकाल पर अकाल पड़ते थे। लोग महामारी, भूखमरी से काल के ग्रास में चले जाते थे। क्रांति के बाद मजदूर-किसान व आम जनता ने जो महसूस किया, वह कोई स्वर्ग की कल्पना से कम नहीं था। लोग खुली हवा में सांस लेने लगे थे। हर तरह गैर-बराबरी, शोषण, जुल्म और अन्याय समाप्त हो गया था। भुखमरी, वेश्यावृत्ति , भिक्षावृत्ति, महंगाई, बेरोजगारी, बेइलाज होने वाली मौत और अशिक्षा की समस्या खत्म हो गई थी। जनता खुशहाल थी। सबको रोटी-कपड़ा-मकान मिलता था। महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा मिला था। जब दुनिया के तमाम पूंजीवादी देश भंयकर मंदी के दौर से गुजर रहे थे तब समाजवादी देश रूस विकास के नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा था। ये सब क्रांति के महानायक लेनिन और उनके बाद क्रांति को आगे बढ़ाने वाले महान स्टालिन के नेतृत्व में सम्भव हुआ।

आज हमारे देश में जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें जनता की समस्यायें दिनोदिन बढ़ती जा रही हैं। आम जनता की खरीद शक्ति घटती जा रही है। सरकारें जनता के गाढ़े खून-पसीने की कमाई को पूंजीपतियों को कर्ज देकर उसे माफ करती जा रही है। किसानों की जमीनें ओने-पौने दामों में लेकर पूंजीपतियों को दे रही है। किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर श्रमिकों के हितों चोट पहुंचाई जा रही है। शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली आदि सभी को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।

ऐसे में आंदोलन और क्रांति ही जनता को हर तरह के जुल्म और अन्याय से मुक्ति दिला सकती है। इसके लिए क्रांतिकारी विचार, सिद्धांत, क्रांतिकारी पार्टी होना आवश्यक है। हमारे सामने मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष का चिन्तन एक सर्वोत्तम विचार है। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ही भारत की एकमात्र सही क्रांतिकारी पार्टी है जो मेहनतकशों को सही दिशा दे रही है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने और अपनी ज्वलंत समस्याओं को लेकर जोरदार जनान्दोलन खड़ा करने की अपील की।

कार्यक्रम का समापन अन्तर्राष्ट्रीय गीत से हुआ। प्रतिभा नायक, महासचिव, एआईडीवाईओ भी मौजूद रही।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503